

3. यदि पेंशनग्राही का बैंक में खाता खुला हुआ है खोल लिया जाय तो बैंक के माध्यम से । ऐसे मामलों में पेंशन-प्राप्तकर्ता को प्रतिमाह एक बिल बनाना पड़ेगा और इसे अपने बैंक को प्रस्तुत करना पड़ेगा, जो खजाने अथवा उप-खजाने से उसकी और से पेंशन वसूल करेगा और उसके खाते में जमा करेगा ।

अवधि : अविवाहित पुत्रियों के मामलों को छोड़कर यह पेंशन उसके प्राप्तकर्ता के जीवन काल के लिए है । अविवाहित पुत्रियों के मामले में, उनके विवाहिक होने अथवा अन्यथा स्वावलम्बी हो जाने के बाद पेंशन तुरन्त बन्द कर दी जाएगी । पेंशन-प्राप्त कर्ता की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी पेंशन के लिए अन्वया प्राप्त होने पर भी स्वतः इस पेंशन के उत्तराधिकारी नहीं होंगे । उन्हें पेंशन प्राप्तकर्ता की मृत्यु के संवत् के साथ नया आवेदनपत्र देना पड़ेगा और उनके आवेदनपत्र पर पेंशन योजना की शर्तों के अनुसार विचार किया जाएगा ।

टिप्पणी :-- (1) पेंशन योजना 15 अगस्त, 1972 से आरम्भ हुई है । 14 अगस्त, 1973 को या उससे पहले प्राप्त आवेदनपत्रों पर 15 अगस्त, 1972 से पेंशन स्वीकृत की जाएगी । उसके बाद प्राप्त आवेदनपत्रों पर पेंशन के सम्बन्ध में प्राप्त होने की तारीख से विचार किया जाएगा ।

(ii) आवेदन पत्र प्राप्त करने की आखिरी तारीख 31-3-1974 निर्धारित की गई थी । क्योंकि बड़ी संख्या में आवेदनपत्र अभी तक प्राप्त हो रहे हैं । अतः यह निर्णय लिया गया कि 30-4-1979 के बाद इस प्रकार के आवेदन पत्रों पर विचार न किया जाय चाहे वे सोधे प्राप्त हों या राज्य सरकार के माध्यम से प्राप्त हों ।

(iii) योजना उन स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन देने के लिए है जिन्हें आर्थिक सहायता की आवश्यकता है । स्वतन्त्रता सेनानियों या उनके परिवारों की आर्थिक दशा पर विचार करने के पश्चात् पेंशन स्वीकृति की जाएगी । केवल वे ही पेंशन स्वीकृति के भात हैं जिनकी आय समी-चोतों से 5000/- रुपए से कम है ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के 25वें प्रतिवेदन को कार्यान्वित करना

5311. श्री भोखाभाई : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के लोक सभा को पेश किए गए 25वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों सहित

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त द्वारा अब तक कुल कितनी सिफारिशें कार्यान्वित की गई हैं ;

(ख) केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा अलग-अलग उनमें से कितनी सिफारिशें कार्यान्वित कर दी गई हैं ; और

(ग) क्या इन सिफारिशों के कार्यान्वयन लिए अलग सैल को स्थापना का प्रश्न उनके संज्ञालय के विचाराधीन है ?

गृह मंत्रालय से राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकडवाणा) : (क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने अपने 25वें वार्षिक प्रतिवेदन में लगभग 4480 सिफारिशें की हैं ।

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के 25वें वार्षिक प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को उचित कार्यवाही के लिए सम्बद्ध केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के ध्यान में लाया गया है ।

पिछड़ा वर्ग आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग

(ग) जी हां, श्रीमान् :

5312. श्री भोखाभाई : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत एक से अधिक बार पिछड़ा वर्ग आयोगों का गठन किया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने आयोगों की नियुक्ति की गई है और कब-कब ?

(ग) क्या संविधान के अनुच्छेद 339 में अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग गठित करने के बारे में भी उल्लेख है ; और

(घ) यदि हां, तो कब तक इस प्रकार का आयोग गठित करने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय से राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकडवाणा) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) भारत सरकार ने संविधान की धारा 340 के अधीन दो पिछड़े वर्ग आयोग नियुक्त किए हैं । एक आयोग की नियुक्ति 29 जनवरी, 1953 को और दूसरे की 1 जनवरी, 1979 को की गई थी ।

(ग) जी हां, श्रीमान् ।

(घ) 28 अक्टूबर, 1960 को "अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति आयोग" नाम से राष्ट्रपति ने एक आयोग नियुक्त किया था । दूसरा आयोग नियुक्त करने के लिए आवश्यकता महसूस नहीं की गई है ।

स्कूटरों का उत्पादन उनकी मांग तथा क्षमता

5313. श्री मूल चन्द डागा : क्या उद्योग मंत्री

यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कम्पनीवार स्कूटरों की वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है ;

(ख) देश में स्कूटरों की वार्षिक मांग कितनी है; और

(ग) कम निर्माण क्षमता के क्या कारण हैं और मांग को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जाएगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) योजना आयोग द्वारा परिवहन, मिट्टी हटाने की मशीनों तथा कृषि मशीनों के सम्बन्ध में नियुक्त किए गए कार्यकारी दल ने 1980-81 में 3 लाख स्कूटरों की मांग होने का अनुमान लगाया है ।

(ग) तकनीकी तथा वित्तीय समस्याओं के कारण कुछ एककों में क्षमता का अपेक्षाकृत कम उपयोग हो रहा है । केन्द्रीय सरकार का उपक्रम स्कूटर इण्डिया लि० अपनी उत्पादन सम्बन्धी समस्याओं पर कानून पाल तथा योजना उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठा रहा है ।

विद्यमान लाइसेंस प्राप्त तथा अधिष्ठापित क्षमतायें मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं ।

विवरण

क्रम संख्या	एकक का नाम	वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता (नग)
1.	मै० आटोमोबाइल प्रोडक्ट्स आफ इण्डिया लि० बम्बई	39,000
2.	मै० बजाज, आटो लि०, पूना	1,00,000
3.	मै० स्कूटर्स इण्डिया लि० लखनऊ	80,000
4.	मै० एस्कोर्ट लि० फरीदाबाद	*
5.	मै० महाराष्ट्र स्कूटर्स लि० पूना	24,000
6.	मै० गुजरात स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि०, अहमदाबाद	3,000
7.	मै० अरावली स्वचालित वाहन लि०, अलवर	3,000
8.	मै० आंध्र प्रदेश स्कूटर्स लि०, हैदराबाद	} 45,000**
9.	मै० पंजाब स्कूटर्स लि० नाशा	
10.	मै० बिहार स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि० पटना	

11. मै० कर्नाटक स्कूटर्स लि०, बंगलौर }
12. मै० वेस्ट बंगाल स्कूटर्स लि० }
कलकत्ता

* 24,000 मोटर साइकिलों की कुल क्षमता के अन्दर । किन्तु उन्होंने स्कूटरों का उत्पादन पह ही बन्द कर दिया है ।

** मै० स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड के लाइसेंस-धारियों अर्थात् आंध्र प्रदेश स्कूटर्स, कर्नाटक स्कूटर्स वेस्ट बंगाल स्कूटर्स बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन तथा पंजाब स्कूटर्स की क्षमता स्कूटर्स इण्डिया लि० (एस० आई० एल०) द्वारा पावर पैको की सलाई पर निर्भर है ।

मै० पंजाब स्कूटर्स लि० ने स्कूटरों का उत्पादन बन्द कर दिया है ।

स्कूटरों के नये कारखानें खोलना

5314. श्री मूल चन्द डागा: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में स्कूटर बनाने के कारखाने देश में स्कूटरों की मांग को पूरा करने में समर्थ हैं ;

(ख) क्या सरकार का स्कूटरों के निर्माण में वृद्धि करने के लिए और कारखानों को खोलने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इन कारखानों को देश में किन किन स्थानों पर खोलने का विचार है तथा उनका अनुमानित वार्षिक उत्पादन क्षमता क्या होगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) देश में स्कूटर बनाने के लिए लाइसेंस प्राप्त क्षमता मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझी जाती है । फिर भी बजाज और प्रिया मेक के स्कूटरों जैसे उपभोक्ता अधिक पसन्द करते हैं, की प्रतीक्षा सूची है ।

(ख) जो, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

News Item "Chambal Dacoits use Pak Bullets"

5315. SHRI R. K. MHALGI: Will Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have noted a news item published in "Sunday Standard" (Bombay) dated the